



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 475]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 25, 2010/भाद्र 3, 1932

No. 475]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 25, 2010/BHADRA 3, 1932

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2010

सा.का.नि. 704(अ).—केन्द्रीय सरकार, रबड़ अधिनियम, 1947 (1947 का 24) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रबड़ नियम, 1955 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रबड़ (संशोधन) नियम, 2010 है।

(2) ये नियम राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को प्रभावी होंगे।

2. रबड़ नियम, 1955 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में परिभाषा से संबंधित नियम 2 में—

(i) उप-नियम (viii-क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“रबड़ के संसाधन” से अभिप्रेत है,—

“(क) किसी रबड़ पौधे से एकत्रित लैटेक्स को ठोस ब्लॉक या लैटेक्स सांद्र या पेल लैटेक्स क्रेप में तकनीकी रूप से विनिर्दिष्ट रबड़ में अथवा तकनीकी रूप से विनिर्दिष्ट रबड़ के किसी अन्य रूप में परिवर्तित करना; और

(ख) स्क्रेप रबड़, शीट रबड़ या क्रेप रबड़ के विभिन्न रूपों को तकनीकी रूप से विनिर्दिष्ट रबड़ के ठोस ब्लॉक रूप या उसके किसी अन्य रूप में परिवर्तित करना”;

(ii) उप-नियम (xi) में “पचास एकड़” शब्दों के स्थान पर “दस एकड़” शब्द रखे जाएंगे;

(iii) उप-नियम (xi-क) में “भारतीय मानक संस्था” शब्दों के स्थान पर “भारतीय मानक ब्यूरो” शब्द रखे जाएंगे।

3. “बोर्ड की रचना एवं रिक्तियाँ भरने का तरीका” से संबंधित उक्त नियम, 1955 के नियम 3 में विद्यमान नियमों के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात्:—

**"बोर्ड का गठन एवं रिक्तियाँ भरने की रीति"**

- (1) बोर्ड, अध्यक्ष एवं धारा 4 की उपधारा 3 के खंड (ख) से खंड (च) में निर्धारित विभिन्न हितों व प्राधिकारों के प्रतिनिधित्व करने वाले सत्ताइस अन्य सदस्यों से मिल कर बनेगा।
  - (2) तमिलनाडु राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले दो सदस्यों में एक तमिलनाडु सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट होगा और दूसरा बड़े कृषकों का प्रतिनिधित्व करेगा। बड़े कृषकों के प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति को केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।
  - (3) केरल राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले आठ सदस्यों में से दो सदस्य केरल सरकार द्वारा राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे। दो व्यक्ति केरल राज्य के बड़े उत्पादकों का, तीन व्यक्ति लघु उत्पादकों का और एक व्यक्ति खड़ उत्पादक सोसायटियों का प्रतिनिधित्व करेगा, जिनको केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।
  - (4) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दस व्यक्तियों में से एक व्यक्ति त्रिपुरा राज्य से छोटे कृषकों का, पहले से निर्धारित तीन व्यक्तियों के अतिरिक्त एक व्यक्ति केरल राज्य के छोटे कृषकों का, एक व्यक्ति चक्रानुक्रम आधार पर कर्नाटक, उड़ीसा आदि जैसे गैर-परम्परागत राज्यों के छोटे कृषकों का और एक व्यक्ति अन्य पणधारियों का प्रतिनिधित्व करेगा।
4. उक्त नियमों में नियम 10, 11 और 13 में "कोरम", "बैठक बुलाने का अधिकार" और "परिचालन द्वारा कार्य" से संबंधित क्रमशः "आठ" शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वह आता है "नौ" शब्द रखा जाएगा।
  5. उक्त नियम में बोर्ड एवं समितियों के सदस्यों के यात्रा तथा अन्य भत्तों से संबंधित नियम 16 में उप नियम (5) का लोप किया जाएगा।
  6. उक्त नियमों में, बोर्ड की स्थापना से संबंधित नियम 19 में विद्यमान उपबंधों के स्थान पर निम्नलिखित उपबंध रखे जाएंगे, अर्थात:-

**बोर्ड की स्थापना**

बोर्ड अपनी राय में इसके प्रभावी कार्य निष्पादन हेतु समय-समय पर केन्द्रीय सरकार से बोर्ड की बजट में विशेष प्रावकलन की लभ्यता के अनुसार आवश्यक स्थापनाओं को मंजूर करेंगे।

परंतु कोई पद केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना सृजित नहीं किया जाएगा। समय-समय पर सरकार द्वारा जारी पदों के सृजन पर पाबंदी आदेशों के अधीन रहते यदि तकनीकी पदों के मामले में, वेतन बैंड 3 में ग्रेड वेतन 5400 रुपए प्रतिमास 39,100 रुपए से अधिक है और

गैर तकनीकी पदों के मामले में वेतन बैंड 3 में ग्रेड वेतन 6,600 प्रतिमास 39,100 रूपए से अधिक है।

परंतु यह और कि बाद में बोर्ड के प्रमाणन के अधीन रहते हुए अत्यावश्यकता के मामले में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी पदों के सृजन के विषय पर पाबंदियों का पालन करते हुए प्रतिमास अधिकतम 5400/-रूपए ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड 3 में 39,100/-रूपए तक के वेतन वाले तकनीकी एवं प्रतिमास अधिकतम 6600/-रूपए ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड 3 में 39,100/-रूपए तक के वेतन वाले गैर तकनीकी अस्थायी पदों का सृजन बोर्ड के हित में आवश्यक होगा।

परंतु यह और भी कि सीधी भर्ती वाले व्यक्ति जिसकी विशिष्ट पद के लिए पहचान की गई है, के पद की पुष्टि केवल केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से ही की जाएगी।

7. उक्त नियम में, गृहों के निर्माण आदि के लिए अग्रिमों की मंजूरी से संबंधित नियम 24क में उप नियम (iv) का लोप किया जाएगा।

8. उक्त नियम में, अध्यक्ष के अधिकार से संबंधित नियम 27 के उपनियम (3) में अध्यक्ष के अधिकारों से संबंधित खण्ड (ड.) में "अर्धवार्षिक" शब्द के स्थान पर "वार्षिक" शब्द रखा जाएगा।

9. उक्त नियमों में अध्यक्ष के अधिकारों से संबंधित नियम 27 के उपनियम (4) के खण्ड (i) और (iii) का लोप किया जाएगा।

10. उक्त नियम में, -

(i) नियम 30 के उपनियम (1), क्रमशः नियम 31 और नियम 34 में "सामान्य निधि" शब्द, जहां-जहां वह आते हैं के स्थान पर "खड़ विकास निधि" शब्द रखे जाएंगे।

(ii) पूल निधि से सहायता से संबंधित नियम 30क का लोप कर दिया जाएगा।

11. उक्त नियम के, नियम 33 में, -

(i) "डाक द्वारा" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) खण्ड (ड.) में "हर वित्तीय वर्ष" शब्दों के पश्चात "विवरणी से संबंधित अवधि की समाप्ति के पश्चात 30 दिनों के अपश्चात" शब्द जोड़े जाएंगे;

(iii) खण्ड (च) के अंत में "वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह माह के अपश्चात" शब्द जोड़े जाएंगे।

12. उक्त नियम के, नियम 33क के उपनियम (1) और उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखे जाएंगे, अर्थात:-

"(1) धारा 12 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट देय समय जिस पर बागान स्वामी द्वारा विवरणी प्रस्तुत नहीं की जाती है या ऐसी विवरणी प्रस्तुत की जाती है, बोर्ड के विश्वास का यह कारण है कि वह गलत या त्रुटिपूर्ण है तो बोर्ड द्वारा स्वामी को उनके बागानों में खड़ के उत्पादन से संबंधित सभी या कुछ लेखे प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया जा सकता है तथा यह साबित करना चाहिए कि:-

(क) अगर विवरणी प्रस्तुत न की गई तो उत्पादन नहीं था;

(ख) यदि विवरणी प्रस्तुत की गई तो विवरणी की शुद्धता और पूर्णता।

बोर्ड लेखा की जाँच वैसी पड़ताल करने के पश्चात, जैसा वह ठीक समझे, धारा 12 की उपधारा (2) के अन्तर्गत संदेय रकम निर्धारित करेगा।

(2) किसी भी वर्ष में किसी बागान का उत्पादन पूरे या आंशिक रूप से किसी भी कारणवश निर्धारण से बच गया तो वही प्रक्रिया अपनायी जाएगी।

(3) बोर्ड, इस नियम के अधीन अपनी शक्तियाँ, निदेशक (लाइसेंसिंग और उत्पाद शुल्क) एवं अन्य ऐसे अधिकारियों को जैसा बोर्ड उचित समझे, प्रत्यायोजित करेगा।"

13. उक्त नियमों के नियम 33ख के उप-नियम (2) और उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात, -

"(2) बोर्ड या तो अपने अधिकारियों या राज्य सरकार के अधिकारियों या केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों या अन्य ऐसे अन्य प्राधिकारियों के माध्यम से लेखा की जाँच और ऐसी और जाँच के पश्चात जो वह ठीक समझे ऐसे विनिर्माता द्वारा संदेय उत्पाद शुल्क का निर्धारण करेगा।

(3) यदि किसी कारणवश विनिर्माता द्वारा अर्जित किए गए खड़ का समग्र अंशवा कोई भाग नियम 33(ड.) में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान निर्धारण से बच गया तो निर्धारण के लिए समान प्रणाली अपनाई जाएगी।

(4) बोर्ड, इस नियम के अधीन अपनी शक्तियाँ निदेशक (लाइसेंसिंग और उत्पाद शुल्क) तथा अन्य ऐसे अधिकारियों को जैसा बोर्ड ठीक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगा।"

14. उक्त नियम के नियम 33 घ. में उप-नियम (1) और उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात -

"(1) प्रत्येक विनिर्माता विवरणी सहित नियम 33 (ड.) में विनिर्दिष्ट अवधियों के दौरान उसके द्वारा अर्जित रबड़ की मात्रा के आधार पर ऐसी दर पर जो समय-समय पर अधिसूचित की जा सके उत्पाद शुल्क का विवरणी से संबंधित अवधि के तीस दिन के अपश्चात्, कोर्टायम स्थित बोर्ड के कार्यालय में और नकद अथवा निदेशक (लाइसेंसिंग और उत्पाद शुल्क), रबड़ बोर्ड, कोर्टायम के पक्ष में कोर्टायम में देय भुगतान के साक्ष्य द्वारा समर्थित बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंक के किसी और ढंग द्वारा संदाय करेगा।

(2) यदि कोई विनिर्माता निर्धारित समय के भीतर उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन देय राशि का संदाय करने में असफल रहता है तो वह चूक की तारीख से प्रेषण की तारीख तक, बोर्ड द्वारा निर्धारित ऐसी दर पर जो, प्रति मास दो प्रतिशत से अनधिक होगी, ब्याज का भुगतान कोर्टायम स्थित बोर्ड के कार्यालय में नकद अथवा निदेशक (लाइसेंसिंग एवं उत्पाद शुल्क), रबड़ बोर्ड, कोर्टायम के पक्ष में कोर्टायम में देय मनीआर्डर या बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंक के जरिए संदाय के किसी अन्य ढंग द्वारा संदाय करेगा।

(3) यदि कोई विनिर्माता, उप नियम (1) में निर्धारित तारीख के भीतर रकम का संदाय करने में असफल रहता है, तो बोर्ड, भू-राजस्व की बकाया राशि के रूप में ब्याज एवं संग्रहण की लागत के साथ बकाया रकम की वसूली के लिए केन्द्रीय सरकार अथवा संबंधित राज्य सरकार को इस मामले की रिपोर्ट दे सकता है।"

15. उक्त नियमों के, बोर्ड के लेखे से संबंधित नियम 35 में, -

"(i) सामान्य एवं पूल निधि" शब्दों के स्थान पर "रबड़ विकास निधि" शब्द रखे जाएँगे;

(ii) उप नियम (1) में "सामान्य निधि" शब्दों के स्थान पर "रबड़ विकास निधि" शब्द रखे जाएँगे;

(iii) नियम 35 के उप-नियम (3) में विद्यमान नियम के स्थान पर "प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् विवरण को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा" रखा जाएगा।

16. उक्त नियम में, नियम 36 का लोप किया जाएगा।

17. उक्त नियम में बोर्ड की निधियों का बैंकों में जमा तथा ऐसी निधियों के निवेश से संबंधित नियम 37 के उप नियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्, -

"ऐसे चेक तथा जमा करने के सभी आदेश या निवेश या जमाओं की निकासी या निवेश या बोर्ड की निधि का किसी भी तरह का उपयोग निदेशक, वित्त या बोर्ड द्वारा इस के लिए प्राधिकृत बोर्ड

3347 4/10-2

के अन्य किसी अधिकारी के हस्ताक्षर तथा अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर से ही किया जाएगा ।"

18. उक्त नियम में नियम 38 का लोप किया जाएगा ।

19. उक्त नियम में नियम 41 का लोप किया जाएगा ।

20. उक्त नियम में अनुज्ञापत्र को प्रति संधत या रद्द करने का अधिकार" से संबंधित नियम 42 में अंत में उल्लिखित "यदि वह आवश्यक विवरणियां प्रस्तुत नहीं करता अथवा यदि वह अनुज्ञापत्र में किसी शर्त का उल्लंघन करे" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा; अर्थात्,-

"यदि वह अधिनियम के किसी उपबंध अथवा अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम अथवा अनुज्ञप्ति की किसी शर्त का उल्लंघन करता है" ।

21. उक्त नियमों में "रबड़ के अन्तर राज्यीय परिवहन से संबंधित घोषणा" से संबंधित नियम 43 ख में:-

(i) उप नियम (1) में "एक राज्य से दूसरे राज्य" शब्दों के स्थान पर "एक राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र से दूसरे राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उप नियम (2) के स्थान पर,-

"इस निमित्त बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत बोर्ड के किसी अधिकारी, अथवा इस संबंध में सरकार द्वारा प्राधिकृत केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों के अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर पारेषक, रबड़ का परिवहन करने वाला व्यक्ति और पारेषिती घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा", को रखा जाएगा ।

22. उक्त नियमों में लाइसेंस शुल्क से संबंधित नियम 45 के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात् -

"इन नियमों के अधीन अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए बोर्ड निम्नलिखित दरों पर एक वर्ष या उसके भाग के लिए फीस का उद्ग्रहण करेगा:-

(क) विनिर्माता को 100 किलोग्राम से अधिक, परंतु 4 टन से अनधिक रबड़ की खरीद हेतु - 100/-रुपए प्रति अनुज्ञप्ति;

(ख) विनिर्माता को 4 टन से अधिक, रबड़ की खरीद के लिए - 250/-रुपए प्रति अनुज्ञप्ति;

(ग) व्याहारी - 250/-रुपए प्रति अनुज्ञप्ति;

(घ) प्रसंस्करणकर्ता को प्रसंस्करण के लिए रबड़ के अधिग्रहण एवं इस प्रकार अधिग्रहित रबड़ की बिक्री - 250/-रुपए प्रति अनुज्ञप्ति; और

(ड.) प्ररूप ड. में विधिमान्य अनुज्ञप्ति धारक विनिर्माता द्वारा प्ररूप ड. में विधिमान्य अनुज्ञप्ति धारक विनिर्माता दूसरे विनिर्माता को आपात स्थिति में रबड़ की बिक्री के लिए 100/-रुपए प्रति अनुज्ञप्ति

23. उक्त नियमों में रबड़ के श्रेणीकरण और विपणन से संबंधित नियम 48 में विद्यमान नियम के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, -

(1) नियम 39क में निर्दिष्ट प्रसंस्करणकर्ता और प्रत्येक व्यक्ति ऐसे मानकों के अनुरूप अपने उत्पादों का श्रेणीकरण और विपणन करेगा, जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(2) किसी भी सम्पदा के स्वामी अथवा व्यौहारी अथवा प्रसंस्करणकर्ता अथवा विनिर्माता अथवा आयातकर्ता अथवा निर्यातकर्ता द्वारा खरीदा गया, बेचा गया अथवा अधिग्रहित अथवा व्यपगत किया गया अथवा कब्जे में रखा गया तकनीकी दृष्टि से विनिर्दिष्ट रबड़ ऐसे मानकों के अनुरूप होगा जिन्हें भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए।

(3) उप नियम (1) के अधीन अधिकथित निर्धारित गुणवत्ता मानदण्डों का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए बोर्ड का कोई भी अधिकारी जिसे अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, किसी सम्पदा के स्वामी, व्यौहारी, प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता, आयातकर्ता अथवा निर्यातकर्ता द्वारा बेचे गए अथवा अन्यथा अधिग्रहित किए गए अथवा व्यपगत किए गए अथवा कब्जे में रखे गए रबड़ का निरीक्षण किसी भी उचित समय पर कर सकता है।

24. उक्त नियमों में नियम 46 का लोप किया जाएगा।

25. उक्त नियमों में पहली अनुसूची में प्ररूप -क, प्ररूप -च, प्ररूप -छ तथा प्ररूप -झ का लोप किया जाएगा।

26. उक्त नियमों में दूसरी अनुसूची का भी लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 2/1/2007-बागान (ग)]

ए. के. मंगोत्रा, अपर सचिव

टिप्पण :-

- (i) सं. सा.का.नि. 1497, तारीख 27 सितम्बर, 1976
- (ii) सं. सा.का.नि. 553, तारीख 18 अप्रैल, 1978
- (iii) सं. सा.का.नि. 163, तारीख 21 जनवरी, 1982
- (iv) सं. सा.का.नि. 1033(अ), तारीख 31 दिसम्बर, 1987
- (v) सं. सा.का.नि. 716(अ), तारीख 20 जून, 1988
- (vi) सं. सा.का.नि. 561(अ), तारीख 5 जुलाई, 1994
- (vii) सं. सा.का.नि. 897(अ), तारीख 12 दिसम्बर, 2001
- (viii) सं. सा.का.नि. 760(अ), तारीख 15 अक्टूबर, 2009

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2010

G.S.R. 704(E).—In exercise of the powers conferred by section 25 of the Rubber Act, 1947 (XXIV of 1947), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Rubber Rules, 1955, namely:—

1. (1) These rules may be called the Rubber (Amendment) Rules, 2010.
- (2) These rules shall come into force on the date of the Publication of this notification in the Official Gazette.
2. In the Rubber Rules, 1955, (hereinafter called the said rules), in rule 2, relating to definition, -
  - (i) for sub-rule (viii-a), the following shall be substituted, namely,-

“Processing of rubber” means,-

    - (a) conversion of field latex of any rubber plant into technically specified rubbers in solid block or latex concentrates or pale latex crepe or any other form of technically specified rubber; and
    - (b) conversion of various forms of scrap rubber, sheet rubber or crepe rubber into technically specified rubbers in solid block or any other form of technically specified rubber.”;
  - (ii) in sub rule (xi), for the words “fifty acres” the words “ten hectares”, shall be substituted;
  - (iii) in sub rule (xi-a) for the words “Indian Standards Institution” the words “Bureau of Indian Standards”, shall be substituted.
3. In rule 3 of the said rules, 1955, relating to “Constitution of the Board and manner of filling vacancies”, for the existing rules the following shall be substituted, namely,-

“Constitution of the Board and manner of filling vacancies”

  - (1) The Board shall consist of the Chairman and twenty seven other members representing the different interests and authorities specified in clauses (b) to (f) of Sub-section 3 of Section 4.



(2) Of the two members to represent the State of Tamil Nadu, one shall be nominated by the Government of Tamil Nadu, and the other shall represent *the large growers*. The person representing large growers shall be nominated by the Central Government.

(3) Of the eight members to represent the State of Kerala., two persons shall be nominated by the Government of Kerala to represent that State. Two persons shall represent the large growers in the State of Kerala, three persons the small growers and one person the Rubber Producers Societies.

(4) Of the ten persons to be nominated by the Central Government one person shall represent small growers from the State of Tripura, one person shall represent small grower from the state of Kerala in addition to three already provided for, one person shall represent small grower from other non traditional states like Karnataka, Orissa, etc. on a rotation basis and one person shall represent the other stake holders.

4. In the said rules, in rules 10, 11 and 13 on "Quorum", "Power to call meetings" and "Business by circulation" respectively for the word "eight", wherever it occur the word "nine" shall be substituted.

5. In the said rules, in rule 16 relating to Travelling and other allowances to members of the Board and its Committees, sub-rule (5) shall be omitted.

6. In the said rules, in rule 19, relating to the Board's Establishment, for the existing provisions, the following shall be substituted, namely,-

#### "Board's Establishment

The Board may from time to time subject to the availability of specific provision in the budget estimate of the Board as sanctioned by the Central Government, sanction such establishment as may in its opinion, be necessary for the efficient performance of its functions.

Provided that no post shall be created without the previous sanction of the Central Government, if the maximum pay of the post exceeds Rs.39, 100/- in the Pay Band 3 with the grade pay Rs.5400/- per month in the case of technical post and Rs.39, 100/- in the Pay Band 3 with the grade pay Rs.6,600/- per month in the case of non-technical posts, subject to observance of the ban orders for creation of posts issued by the Government from time to time:

3347 5/10-3

Provided further that in case of exigencies, temporary posts which would need to be created in the interest of the Board and the maximum pay of which does not exceed *Rs.39,100/- in the Pay Band 3 with the grade pay Rs.5400/-* per man sum in the case of technical posts and *Rs.39100/- in the Pay Band 3 with the grade pay Rs.6,600/-* per month in the case of non-technical posts, subject to observance of the ban orders for creation of posts issued by the Government from time to time, may be created by the Chairman, subject to certification by the Board, subsequently:

Provided also further that the confirmation to a key post of a direct recruit who has been identified to that particular post shall be made only with the prior approval of the Central Government.

7. In the said rules, in rule 24A, relating to Grant of advances for building etc., of houses, sub-rule (iv) shall be omitted.

8. In the said rules, in rule 27, relating to Powers of the Chairman, in sub-rule (3), in clause (e) relating to powers of the Chairman, for the words "a half yearly" the words "an annual", shall be substituted.

9. In the said rules, in rule 27, relating to Powers of the Chairman, clauses (i) and (iii) of sub rule (4) shall be omitted.

10. In the said rules,-

(i) in sub-rule (1) of rule 30, in rule 31 and in rule 34 respectively for the words "General Fund", the words "Rubber Development Fund", wherever they occur shall be substituted.

(ii) rule 30 A, relating to Assistance from Pool Fund shall be omitted.

11. In the said rules, in rule 33, -

(i) the words "By Post" shall be omitted ;

(ii) in clause (e) after the words each financial year, the words "Not later than 30 days after the expiry of the period to which the return relates to" shall be added;

(iii) in clause (f), at the end, the words "not later than six months from the end of the financial year" shall be added.

12. In the said rules, in rule 33A, for sub- rules (1) and (2) the following shall be substituted, namely,-

“(1).If any owner of an estate fails to furnish in due time the return referred to in sub-section (4) of section 12 or furnishes a return which the Board has reason to believe is incorrect or defective, the Board may serve a notice on the owner calling upon him to produce all or any of his accounts relating to production of rubber on his estates and to prove

(a) if no return has been submitted, that there was no production

(b) if a return has been submitted, the correctness and completeness of the return.

The Board shall, after checking the accounts and after making such further enquiry as it deems fit, assess the amount payable under Sub-section (2) of Section 12,

(2) The same procedure shall be followed if for any reason the whole or any part of the production in an estate has escaped assessment in any year.

(3) The Board may delegate its powers under this rule to the Director (Licensing and Excise Duty) and to such other officers of the Board as it deems fit.”

13. In the said rules, in rule 33B for sub- rules (2) and ( 3), the following shall be substituted, namely,-

“(2)The Board shall, after checking the accounts and after making such further enquiry as it deems fit, either through its own officers or through officers of the State Government or Central Government or such other authorities, assess the amount of excise duty payable by such manufacturer.

(3) The same procedure shall be followed if for any reason the whole or any part of the rubber acquired by a manufacturer has escaped assessment during the period specified in rule 33(e).

(4)The Board may delegate its powers under this rule to the Director (Licensing and Excise Duty) and such other officers of the Board as it deems fit.”

14. In the said rules, in rule 33D, for sub rules (1) and (2) the following shall be substituted, namely,-

“(1) Every manufacturer shall pay to the Board the duty of excise at such rate, as may be notified from time to time, on the quantity of the rubber acquired by him during the periods specified in rule 33(e) along with the return, not later than thirty days after the period to which the return relates to, either in cash at the Board's office at Kottayam or by money order or by bank draft or by any mode of payment through bank, payable at Kottayam to the Director (Licensing and Excise Duty), Rubber Board, evidenced by proof of payment.

(2) If any manufacturer fails to pay the amount due under sub-rule(1) above within the time prescribed, he shall pay interest at such rate as may be fixed by the Board not exceeding two percent per month from the date of default till the date of remittance either in cash at the Board's office at Kottayam or by money order or by bank draft or through any mode of payment through bank payable at Kottayam to the Director (Licensing and Excise Duty) Rubber Board.

(3) If any manufacturer fails to pay the amount within the date prescribed in sub-rule (1), the Board may report the fact to the Central Government or the State Government concerned for recovery of the outstanding amount with interest and cost of collection, as an arrear of land revenue.”

15. In the said rules, in rule 35 relating to Accounts of the Board,-

“(i) for the words “General and Pool Funds” the words “the Rubber Development Fund”, shall be substituted;

(ii) in sub-rule (1) for the words “General Fund” the words “the Rubber Development Fund”, shall be substituted:

(iii) in sub-rule (3) of rule 35, the existing rule, “After the close of each year the statement shall be placed before the Board”, shall be substituted.

16. In the said rules, rule 36 shall be omitted.

17. In the said rules, in rule 37 relating to Deposit of funds of the Board in banks and the investment of such funds, for sub-rule (5), the following shall be substituted, namely,-

“Such cheques and all orders for making deposits or investments or withdrawals of deposits of investments or for the disposal in any other manner of the funds of the Board shall be signed by the Director of Finance or any

other Officer of the Board, duly authorized by the Board in this behalf and countersigned by the Chairman or any other officer authorized by the Chairman”.

18. In the said rules, rule 38 shall be omitted.

19. In the said rules, rule 41 shall be omitted.

20. In the said rules, in rule 42 relating to “Power to revoke and cancel licence”, for the words at the end, “if he fails to submit the necessary returns or if he contravenes any of the conditions of the licence”, the following shall be substituted, namely,-

“if he contravenes any of the provisions of the Act or rule made under the Act or conditions of the licence”.

21. In the said rules, in rule 43B relating to “Declaration regarding Inter State transport of rubber”, -

(i) in sub- rule (1), for the words “from one State to another State” the words from one state or Union Territory to another State or Union Territory”, shall be substituted;

(ii) for sub- rule (2), -

“On demand by any officer of the Board authorized in that behalf by the Chairman of the Board, or any officer of the Central or State Governments authorized in that behalf by that Government, the consignor, the person transporting rubber and the consignee shall produce the declaration”, shall be substituted.

22 In the said rules, for rule 45 relating to Licence Fees, the following shall be substituted, namely,-

“The Board shall levy fees at the following rates for a year or part of a year for issuing licences under these rules to:-

- (a) manufacturer for purchase of rubber exceeding 100 kilograms, but not exceeding 4 tonnes - Rs.100/- per licence;
- (b) manufacturer for purchase of rubber exceeding 4 tonnes, Rs.250/- per licence;
- c) dealer Rs. 250/- per licence;

334749/10-4

- d) processor for acquisition of rubber for processing and sale of rubber so acquired, Rs.250/- per licence; and
- e) manufacturer holding a valid licence in form E for selling rubber to another manufacturer holding a valid licence in Form E in emergencies, Rs.100/- per licence.”

23 In the said rules, in rule 48 relating to Grading and marketing of rubber, for the existing rule the following may be substituted,-

(1) Every processor and every person referred to in Rule 39A shall grade and market his products in conformity with such standards as are specified by the Bureau of Indian Standards from time to time.

(2) Technically Specified Rubber purchased, sold or otherwise acquired or disposed of or possessed by any owner of estate or dealer or processor or manufacturer or importer or exporter shall be in conformity with such standards as are specified by the Bureau of Indian Standards from time to time.

(3) Any officer of the Board authorized by the Chairman may at any reasonable time inspect the rubber sold or otherwise acquired or disposed of or possessed by any owner of estate, dealer, processor, manufacturer, importer and exporter for the purpose of ensuring strict compliance with the quality standards laid down under sub-rule(1)”

24 In the said rules, Rule 46 shall be omitted.

25 In the said rules, in the First Schedule, Forms A, Form F, Form G and Form I shall be omitted.

26 In the said rules, The Second Schedule shall also be omitted.

[F. No. 2/1/2007-Plant (C)]

A. K. MANGOTRA, Addl. Secy.

**Foot Note:** The principal rules were published in the Gazette of India (Extraordinary), Part II, Section 3, Sub-section (i); page 1613, dated the 1st August, 1955, and subsequently amended *vide* the following numbers, namely:—

- (i) No. G.S.R. 1497, dated the 27th September, 1976.
- (ii) No. G.S.R. 553, dated the 18th April, 1978.
- (iii) No. G.S.R. 163, dated the 21st January 1982,
- (iv) No. G.S.R. 1033(E), dated the 31st December, 1987.
- (v) No. G.S.R. 716(E), dated the 20th June, 1988.
- (vi) No. G.S.R. 561 (E), dated the 5th July, 1994.
- (vii) No. G.S.R. 897(E), dated the 12th December, 2001.
- (viii) No. G.S.R. 760(E), dated 15th October, 2009.